प्रेस नोट 28
फरवरी, 2015

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं विधायक श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज मीडिया के सामने निम्नलिखित बयान जारी किया ;

'भाजपा सरकार द्वारा 2015-16 के लिए प्रस्तुत आम बजट आम आदमी व वेतनभोगी तबके के लिए पूर्णतय निराशाजनक, ग्रामीण विकास एवं प्रगति को बाधित करने वाला और निवेश एवं वृद्धि के लिए पूरी तरह नकारात्मक है। इस बजट के जरिये भाजपा का किसान व आम आदमी विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। बजट से यह बात भी साबित हो गई है कि मौजूदा मोदी सरकार पूरी तरह से अमीरों की और अमीरों द्वारा संचालित है।

आम बजट के जरिये वित्त मंत्री के पास बड़े आर्थिक सुधारों, शानदार कृषि वृद्धि दर, रोजगार सृजन, जनकल्याणकारी योजनाओं के संरक्षण, आधारभूत ढांजे की मजबूती और महंगाई दर में कमी लाने का ऐतिहासिक मौका था। वित्त मंत्री ने यह मौका अपने घिसे-पिटे ढर्रे पर पूरी तरह से गंवा दिया है और बजट में किसी भी तरह का कोई ठोस कदम व दिशा दिखाई नहीं देती।

श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली को अब बिना देर किए आम आदमी के 'अच्छे दिन' लाने के लिए अपने सपने को लेकर जवाब देना होगा।

कृषि : सबसे बड़ी भुगतभोगी देश की 62 प्रतिशत आबादी और 49 प्रतिशत कमेरा वर्ग पूरी तरह से कृषि पर जीवन यापन करते हैं। ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में 17 प्रतिशत योगदान देता है। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र की घोरतम उपेक्षा इस बजट में की गई है। 2015 का आर्थिक सर्वे स्वयं इस बात को दर्शाता है कि 2013-14 के दौरान कांग्रेस सरकार में कृषि विकास दर 4.7 से गिरकर 2014-15 में भाजपा के शासन में 1.1 प्रतिशत रह गई है। द�
 ��श
 ��ें कुल अनाज का उत्पादन 2013 के 2650 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2014-15 में 2570 लाख मीट्रिक टन रह जाने की उम्मीद है। यही नहीं, सरकार की कृषि एवं किसान विरोधी नीतियों के चलते 2014-15 में देश में खेती का कुल क्षेत्रफल 33.22 लाख हैक्टयेर घट गया है।

मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान देश में यूरिया का अभूतपूर्व संकट भी गलत नीतियों के कारण जारी है। कांग्रेस सरकार ने जहां जून-अक्तूबर (2013 में) के बीच 43.82 लाख टन यूरिया आयात किया वहीं मोदी सरकार ने 2014 में इसी अवधि के बीच केवल 17.37 प्रतिशत लाख टन यूरिया का आयात किया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि बजट में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने बारे पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है।
 ासत
्तव में मुख्य फसलों जैसे बासमती चावल की कीमतें पिछले साल के 6000-6500 प्रति क्विंटल से घटकर 3200-3300 रुपये प्रति क्विंटल रह गई हैं। इसी तरह कपास के दाम भी एक साल के भीतर 5300-5500 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 3800-4000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं।

कच्चे तेल के दाम मई-2014 के 114 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 54 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं मगर गांवों में इस गिरावट का लाभ आम आदमी और किसानों को देते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने की बजाय इन दोनों पर कस्टम ड्यूटी 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी में चार गुणा बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने में

साल की नब्बे हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। आम आदमी के हितों की कीमत पर
सर
कारी खजाना भरने का यह अब तक का सबसे भयावह उदाहरण है। लोगों के जले पर नमक छिडक़ते हुए वित्त मंत्री ने डीजल व पेट्रोल का रोड सैश भी 2 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि मोदी सरकार ने हवाई ईंधन की कीमत 76.24 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 46.51 रुपये प्रति लीटर कर दी है। सरकार की इस नीति से हवाई ईंधन पेट्रोल व डीजल से भी सस्ता हो गया है। सरकार का ग्रामीण विकास और मनरेगा जैसी नीतियों पर कोई ध्यान नहीं है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 में मनरेगा के लिए 34 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए, जिनमें से केवल 13833 करोड़ रुपये का ही वितरण हो पाया |

ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट वास्तव में घट गया है। मंत्रालय को मनरेगा के लिए 34 हजार 600 करोड़ रुपये मिलाकर मात्र 72 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पूरी आशंका इस बात की है कि मनरेगा का धन एक बार फिर आवंटित नहीं किया जाएगा।

आम आदमी/वेतनभोगी वर्ग बनाम उद्योग जगत
आम आदमी और वेतनभोगी वर्ग बजट के बाद खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत आयकर में कोई राहत नहीं दी गई है। इन वर्गों के लिए बचत पर भी किसी राहत की पेशकश नहीं की गई है। आम आदमी के लिए बहुप्रचारित पेंशन योजना में भी सालाना केवल पांच हजार रुपये के योगदान का प्रावधान किया गया है, वो भी केवल पांच वर्ष के लिए। इस तरह बजट पूरी तरह से अर्थहीन होकर रह गया है। इसके व�
�पर
ित वित्त मंत्री ने औद्योगिक कर में पांच प्रतिशत की कमी करने का वायदा किया है।

महंगाई
महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012 की तुलना में जनवरी 2015 में 5.11 प्रतिशत बढ़ा है। यह बढ़ोतरी भोजन व पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का परिणाम है।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
(i) वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 20 हजार करोड़ रुपये के कोष वाला मुद्रा बैंक किस तरह से मध्यम एवं छोटे उद्योगों के 5 लाख 64 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक उत्पादन में अमूल-चूल परिवर्तन कर देगा।

(ii) वित्त मंत्री का नीति आयोग में 150 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण फंड की स्थापना का वायदा महज एक छलावा है। यही नहीं, सभी तरह के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मात्र एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन पूरी तरह से अपर्याप्त है।

(iii) गांवों में युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन भी एक औपचारिकता ही है।

(iv) वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन के लिए भी कोई रोड मैप बजट में प्रस्तुत नहीं किया है।

(v) देश के वार्षिक रक्षा बजट में मात्र 20 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि सरकार की कथनी और करनी के गंभीर अंतर को दर्शाती है।

(vi) सरकार की मुख्य योजनाएं जैसे 'स्मार्ट सिटी योजना', 'स्वच्छ भारत अभियान', 'सागरमाला', 'नमो गंगे' व 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के लिए धन का आवंटन न किए जाने से साफ है कि यह सरकार नारे देना जानती है, क्रियान्वयन करना नहीं। उदाहरण के लिए देश में 92 करोड़ शौचालयों के निर्माण के लिए 1 लाख 98 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला
कांग्रेस प्रवक्ता एवं विधायक।

BHUPINDER SINGH BHUPI
Spokesman
HKKMC